

महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न से संबंधित सुनीं शिकायतें

महिला आयोग की सदस्य ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए दिव्ये ने महिला जनसुनवाई में प्राप्त हुई 10 शिकायतें, महिला आयोग की सदस्य द्वारा जनजागरूकता चौपाल में जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश हैं कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रकरणों



प्रतिभाग कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में प्रतीभाग कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। बुधवार को मा0 सदस्य 30प्र0 राज्य महिला आयोग पुनर्निर्देशों ने जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न व उनकी समस्याओं से जुड़े मुद्दों के बारे में अधिकारियों से समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जन सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक समस्या, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा व रोजगार आदि संबंधी शिकायत सुनीं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि महिलाओं के उत्पीड़न व महिला से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से किया जाये तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत व ग्रामीण स्तर पर कराया जाये। जिन प्रकरणों में अभी कार्यवाही लंबित है उन्हें भी आयोग के संज्ञान में लाने के

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी का हुआ भव्य स्वागत

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। अखिल भारतीय हिंदू

की इकाइयों का विस्तार किया जाएगा। इसी क्रम महासभा के



महासभा (भारत)के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माननीय अनिल शर्मा के रायबरेली आगमन पर सभी हिंदू महासभा के पदाधिकारी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। औपचारिक बैठक के साथ प्रदेश संयोजक राजेंद्र अवस्थी ने संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप अग्रवाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपते हुए विश्वास जताया गया की संगठन

द्वारा आयोजित आगामी जुलाई और अगस्त के धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों की भी चर्चा की गई। इसी कड़ी में जिला संरक्षण महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा में रायबरेली जनपद से 1 जुलाई को शिव भक्तों का जल्था रायबरेली जनपद से निकलेगा जिनका स्वागत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा किया

वाराणसी के हीरामनपुर में ग्रामीणों ने शराब का ठेका खोलने का विरोध, कहा अस्पताल के पास नहीं खुलने दंगे ठेका

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) वाराणसी। सिंधौरा स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरामनपुर ग्राम में शराब का ठेका खोलने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों में गुस्सा पनप रहा है। उनका कहना है कि जिस मुख्य मार्ग पर ठेका खोला जा रहा है, वहां पर धार्मिक स्थल और अस्पताल हैं। गांव की बहू-बेटियां भी यहां से होकर निकलती हैं। ऐसे में ठेका खोलने से शराबी उन्हे परेशान कर सकते हैं। इसमें कई समस्याएं बताते हुए गांव में शराब का ठेका

नहीं खोले जाने की मांग की है। गांव के ही रहने वाले अंबर कुमार, बजरंगी यादव आदि गांव वालों ने बताया है कि गांव के बाजार में कंपोजिट शराब की दुकान जिसके मालिक राजेश उपाध्याय को शासन द्वारा दारु का ठेका खोलने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा शासन के नियमों को ताक पर रखकर कंपोजिट शराब का ठेका खोलने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। गांव की महिलाओं को खेतोबाड़ी के कार्य के लिए इसी मार्ग से आना जाना होता है। आबकारी नियमों के अनुसार स्कूल व धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकान खोलना वर्जित है, उन्होंने जनहित में महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित कंपोजिट शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग की है। विरोध करने वाले हैं मुख्य रूप से त्रिभुवन, छेदी, रामेश्वर, रीमा, मानसा देवी, भागीरथी देवी आदि के नाम हैं।

योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम, विद्यार्थियों से लेकर हर वर्ग के लिए उपयोगी- निदेशक प्रो डॉ अमिता जैन

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। सई नदी तट स्थित शहीदों का पवन धरती राणा बेनी माधव बख्खा सिंह पार्क बुधवार सुबह योग चेतना, स्वास्थ्य जागरूकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन

निर्माण और योग को जनआंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। डॉ. अमिता जैन ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को समय-समय पर रिचार्ज करते हैं, उसी प्रकार



गई। मातृभूमि सेवा मिशन की ओर से आयोजित पांच दिवसीय विश्व योग महोत्सव एवं जनसंवाद समारोह का शुभारंभ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली की निदेशक प्रोफेसर डॉ. अमिता जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली के संदेश के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़कर आयोजन का विधिवत आगाज किया, इसके साथ ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण भी किया। प्रतिष्ठित संस्थान एम्स रायबरेली का नेतृत्व कर रही निदेशक प्रो. डॉ. अमिता जैन ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। यह व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास का विकास करता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ योग

शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान जरूरी है। योग के लिए दिया गया समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने वाला निवेश है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति के विचारों में संतुलन लाता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मातृभूमि सेवा मिशन के अध्यक्ष रामराज गिरी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन, अनुशासन और आत्मिक शांति का माध्यम है। अवध क्षेत्र मंडल अध्यक्ष भगवत प्रताप सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग निरोगी जीवन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि सेवा मिशन का यह प्रयास जन-जन तक योग पहुंचाने की दिशा में सराहनीय पहल है। मिशन के संस्थापक डॉ. श्रीप्रकाश मिश्र के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस पांच दिवसीय योग महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों, बच्चों, युवाओं और पुरुषों ने सहभागिता की। योग शिविर में स्वस्थ जीवन के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण भी किया गया। आयोजन समिति की ओर से योग शिविर में पहुंचे नन्हे-मुन्हे बच्चों को गुस्कों की किट वितरित की गई। कार्यक्रम में डॉ. विजय रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा, पूर्व

मानसिक रूप से विकसित पति की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा करने का आरोप

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। तहसील रॉबर्ट्सगंज

राजकुमार बच्चों के जीविकोपार्जन की एकमात्र जमीन बचाई जाए पुत्र विश्वनाथ ने पति की



के ग्राम सण्डा, परगना विजयगढ़ निवासी राधा पत्नी काजू उर्फ कामेश्वर ने जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को प्रार्थना पत्र देकर जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। राधा ने बताया कि उनके पति काजू उर्फ कामेश्वर मानसिक रूप से विकसित हैं। उनका इलाज मनोचिकित्सक से चल रहा है। मौजा मरकरी, परगना विजयगढ़, तहसील रॉबर्ट्सगंज में स्थित आराजी संख्या 64 रकबा 1.130 हे0 भूमि का 1/2 अंश पति के नाम माल खर्तौनी में दर्ज है। यही जमीन राधा व उनके बच्चों के जीविकोपार्जन का एकमात्र सहायक है और उस पर उनका कब्जा-दखल है। आरोप है कि वाई नं0 24 कम्पल प्रिंटिंग प्रेस, उत्तर मोहाल,

मानसिक विकसितता का फायदा उठाकर 0.253 हे0 यानी 1 बीघा जमीन का बैनामा बहुत कम कीमत 9 लाख रुपये में अपनी पत्नी निरंजनी सैनी के नाम करा लिया। वहीं बची 0.312 हे0 जमीन का इकरारनामा वास्ते बैनामा मिशन अस्पताल के पास निवासी भू-माफिया ओ के साथ बिना प्रतिफल के कर लिया गया। ग्राम मरकरी में जमीन की कीमत 5 लाख रुपये के आधार पर खर्तौनी में दर्ज है। राधा ने मांग की कि फर्जी दस्तावेज बैनामा व इकरारनामा के आधार पर खर्तौनी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे लोगो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर तत्काल कब्जा रोका जाए, अन्यथा वे बच्चों सहित भूखों मरने को मजबूर हो जाएंगी।

मण्डल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन आज आई0टी0आई0 नैनी में

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। 30प्र0 कौशल

मोटर्स, लावा मोबाइल, क्लिकेट, लेनोवो जैसी इत्यादि 60



विकास मिशन, राजकीय आई0टी0आई0 एवं क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 19 जून, 2026 को राजकीय आई0टी0आई0 नैनी, प्रयागराज में प्रातः 10:00 बजे से एक दिवसीय मण्डल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त मेले में निजी क्षेत्र की कम्पनी टाटा मोटर्स, फिलपकार्ट, रिलाइंस, भारत

कम्पनियों द्वारा लगभग 9000 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जायेगी। रोजगार मेले में जूनियर हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, आई0टी0आई0, डिप्लोमा, बी0टेक, 30प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं।

प्रयागराज सबसे गर्म-तापमान पहुंचा 45डिग्री, तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, गर्मी से लोग परेशान

प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार शाम आई तेज आंधी और बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी ही देर की राहत

का भी असर तेज है। लोग धूप से बचने के लिए बाहर गमछा, टोपी और छाता का सहारा ले रहे हैं। बुधवार को दिनभर तेज धूप रहने के बाद शाम



मिठी, लेकिन गुरुवार सुबह से ही तेज और चटक धूप निकलने के कारण गर्मी का असर फिर बढ़ गया है। सुबह से ही कड़ी धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। शहर में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, इसके पहले 3 दिन से तापमान 40 के ऊपर बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप के कारण लोगों को गर्म हवाओं

विभाग के अनुसार आने वाले समय में मौसम फिर बदल सकता है। विभाग ने तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। हालांकि इसके साथ ही गर्मी का असर भी बना रह सकता है। लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब सभी की निगाहें मानसून की दस्तक पर टिकी हैं, जिससे इस तपस्व से राहत मिलने की उम्मीद है।

विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम का भव्य आयोजन

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने द्वितीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किया प्रतिभाग, 'विकसित भारत संकल्प' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का जन आंदोलन-उद्यान मंत्री, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार जनकल्याण के उद्देश्य से निरंतर कर रही कार्य - दिनेश प्रताप सिंह (आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष एवं प्रदेश सरकार के 09 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामुदायिक केंद्र रातापुर में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं विकास प्रदर्शनी' कार्यक्रम के द्वितीय दिवस राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, 30प्र0 दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोंका, मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान मा0 मंत्री ने सर्वप्रथम सूचना विभाग द्वारा लागाई गई विकास प्रदर्शनी एवं विभिन्न विभागों द्वारा लागाए गए स्टालों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभागों योजनाओं की प्रगति एवं लाभार्थियों को मिल रहे लाभ की जानकारी प्राप्त की। स्टालों के निरीक्षण के समय मा0 मंत्री जी द्वारा तीन बच्चों को अन्नप्रदान कराया गया तथा तीन गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित कर गोद भराई की और उनके

द्वारा आयोजित आगामी जुलाई और अगस्त के धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों की भी चर्चा की गई। इसी कड़ी में जिला संरक्षण महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा में रायबरेली जनपद से 1 जुलाई को शिव भक्तों का जल्था रायबरेली जनपद से निकलेगा जिनका स्वागत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा किया

बनाने का जन आंदोलन है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे उनका लाभ उठा सकें। मंत्री ने कहा कि जनपद के अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी लगन व निष्ठा के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त लाभार्थियों को दिलाने का कार्य कर रहे हैं, आज बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी प्रकार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित किया जाए। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। मंच का संचालन एस0एस0 पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपयुक्त (श्रम रोजगार) प्रमोद सिंह, जिला विकास अधिकारी वर्ण सिंह, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 मुन्शा चन्द्र, उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह, जिला प्रवेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, जिला उद्यान अधिकारी जयराज वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण व लाभार्थीगण उपस्थित रहे।

अमेरिकी नौसेना द्वारा भारतीय वाणिज्य जहाजों पर कार्रवाई पूर्ण हमला और चालक दल के तीन नाविकों की मौत पर वामदलों का प्रतिवाद

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। गुरुवार को कम्प्यूनिस्ट नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अमेरिकी सरकार के खिलाफ विरोध जताया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने होमरुज (जलडमरूमध्य) से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए कार्रवाईपूर्ण हमले, जिसमें भारतीय चालक दल के तीन नाविकों की मौत पर संयुक्त रूप से कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराया और इस सम्बन्ध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति को सम्बोधित जिलाधिकारी को सौंपा। संयुक्त वामदलों द्वारा ज्ञापन में कहा गया कि अमेरिकी शासन की ये कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में मुक्त नौहन

के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व थोपने को कोशिश करने वाले किसी गुट के खिलाफ विरोध जताया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने होमरुज (जलडमरूमध्य) से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए कार्रवाईपूर्ण हमले, जिसमें भारतीय चालक दल के तीन नाविकों की मौत पर संयुक्त रूप से कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराया और इस सम्बन्ध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति को सम्बोधित जिलाधिकारी को सौंपा। संयुक्त वामदलों द्वारा ज्ञापन में कहा गया कि अमेरिकी शासन की ये कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में मुक्त नौहन



की तरह व्यवहार कर रहा है, इसे बदल नहीं किया जा सकता। आगे कहा गया कि भाजपा नीत केन्द्र सरकार स्वतंत्र विदेश नीति से पीछे हटकर अमेरिका की कनिष्ठ साझेदार बनने के कारण अपने कर्तव्यों का घोर उल्लंघन कर रही है। इस घटना पर सरकार की कमजोर प्रतिक्रिया और अमेरिका से माफी मांगवने में उसकी विफलता

विभाग के अनुसार आने वाले समय में मौसम फिर बदल सकता है। विभाग ने तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। हालांकि इसके साथ ही गर्मी का असर भी बना रह सकता है। लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब सभी की निगाहें मानसून की दस्तक पर टिकी हैं, जिससे इस तपस्व से राहत मिलने की उम्मीद है।

मोहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने की पीस कमेटी की बैठक, ताजिया की ऊँचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी, नई परंपरा की अनुमति नहीं-जिलाधिकारी निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन एवं अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद,

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) भी जुलूस में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन अथवा प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी कि जुलूस मार्गों पर लटक रहे अथवा झूले विद्युत तारों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। साथ ही



को जनपद में सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझ कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी (धर्मगुरुओं एवं गणमान्य नागरिकों) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न धर्मगुरुओं, ताजियादारों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर आपसी भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के साथ पर्व मनाने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मोहर्रम पर्व पूरी श्रद्धा, अनुशासन एवं कानून व्यवस्था के दायरे में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि ताजिया की ऊँचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी तथा किसी भी स्थिति में पेड़ों की डालियों की छटाई नहीं की जाएगी। नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी तथा पूर्व से चिन्हित कर्बला स्थलों पर ही ताजिया दफन किए जाएंगे। किसी ने कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित की जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को दें। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोहर्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देशित किया कि डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएं। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से यातायात व्यवस्था में सहयोग करने तथा प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया

सफ़ैशी अधिनियम के तहत बैंक ऑफ इंडिया शाखा राबट्सगंज को दिलाया गया कब्जा

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) अधिकारियों ने बताया कि ऋण राबट्सगंज/सोनभद्र। बैंक ऑफ खाते में लगातार चूक होने के



इंडिया शाखा राबट्सगंज द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही के अंतर्गत सफ़ैशी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर संबंधित संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा दिलाने की कार्यवाही संपन्न हुई। बैंक कारण नियमानुसार सफ़ैशी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। कब्जा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया प्रशासन एवं पुलिस की मौजूदगी में संपन्न कराई गई। सूरज वर्मा एडवोकेट-जनपद एवं सत्र न्यायालय, सोनभद्र सफ़ैशी अधिनियम के तहत बैंक ऑफ इंडिया शाखा राबट्सगंज को मजिस्ट्रेट के आदेश पर संपत्ति का विधिक कब्जा दिलाया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा 19 जून को सोनभद्र दौरे पर, मंगुराही, मधुपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) कृषि भवन परिसर, मंगुराही, तेन्दू, सोनभद्र पहुंचेंगे। मा0 मंत्री जी अपरान्ह 01:30 बजे से 02:20 बजे तक आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम "12 साल विश्वास के, विकास के एवं जन कल्याण के" के अंतर्गत प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा तथा किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम उपरांत मा0 मंत्री जी अपरान्ह 02:20 बजे मंगुराही, मधुपुर से प्रस्थान कर 3:20 बजे अहरोरा, मिर्जापुर पहुंचेंगे, जहां अल्प विश्राम एवं भोजन के उपरांत 03:45 बजे पुनः प्रस्थान करेंगे।



के मा0 राज्य मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा दिनांक 19 जून, 2026 को जनपद सोनभद्र के भ्रमण पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मा0 मंत्री जी प्रातः 11:30 बजे वाराणसी स्थित सिकेट हाउस से प्रस्थान कर अपरान्ह 01:30 बजे

राष्ट्रीय लोक दल युवा विवेक चतुर्वेदी को प्रदेश महासचिव की मिली जिम्मेदारी

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) कार्यलय पहुंचकर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय



के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर संगठन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से सोनभद्र निवासी विवेक चतुर्वेदी को युवा प्रदेश राष्ट्रीय लोक दल का महासचिव मनोनीत किया है। उनके मनोनीयन पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्साह का माहौल है। अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने हेतु लखनऊ प्रदेश दुबे की गरिमामयी उपस्थिति में युवा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल के द्वारा विवेक चतुर्वेदी को नियुक्ति पत्र सौंप कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता से युवा रालोद को नई ऊर्जा मिलेगी तथा पार्टी की नीतियों और विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। विवेक चतुर्वेदी लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत बनाने, युवाओं को जोड़ने तथा संगठन के विस्तार के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनके मनोनीयन पर बधाई देते जिलाध्यक्ष रालोद श्रीकांत त्रिपाठी ने उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। समस्त जानकारी जिला मिडिया प्रभारी विकास पाण्डेय ने दिया।

महंगाई-वेतन विसंगति से त्रस्त श्रमिकों को तत्काल राहत दे सरकार, आशा-आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़े भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा 22 सूत्रीय मांगपत्र, संविदा कर्मियों के शोषण व पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मांग

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। कर्मचारियों व श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ, जिला सोनभद्र ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित 22 सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी को देखकर बुलंद की आवाज किया विरोध प्रदर्शन। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दशा राम यादव ने की और मंच संवालन जिला मंत्री एल. पी. शुक्ल ने किया। प्रदेश मंत्री अरुण कुमार दुबे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बी. डी. विश्वकर्मा व विभाग प्रमुख अश्विनी कुमार शुक्ल, कुषेंद्र शुक्ल मुख्य रूप से मौजूद रहे। आशा, आंगनवाड़ी, एनएचएम, सफाई कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ऊर्जा क्षेत्र, असंगठित श्रमिक सहित विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश मंत्री अरुण कुमार दुबे ने कहा कि श्रमिक, कर्मचारी व संविदा कर्मी महंगाई, वेतन विसंगति, सामाजिक सुरक्षा के अभाव



और रिक्त पदों पर भर्ती न होने से परेशान हैं। संविदा कर्मियों का शोषण गंभीर मुद्दा है, सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। विभाग प्रमुख अश्विनी कुमार शुक्ल ने आशा, आंगनवाड़ी व एनएचएम कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय व सामाजिक सुरक्षा देने, संविदा-आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली बनाने की मांग की। बी. डी. विश्वकर्मा ने 2023 की हड़ताल में शामिल ऊर्जा कर्मियों पर उत्पीड़न रोकने, 108-102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली और चीनी मिल-डिस्टिलरी कर्मियों के लंबित वेतन पुनरीक्षण की मांग उठाई। ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, आशा-आंगनवाड़ी मानदेय बढ़ाने, बैंकों में पांच दिवसीय बैंकिंग, नगर निकायों में स्थायी सफाई कर्मियों की भर्ती, पत्रकारों व असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने सहित 22 मांगें शामिल हैं। जिलाध्यक्ष दशा राम यादव ने कहा कि मजदूर संघ श्रमिक हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहेगा।



NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी

फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड
कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है। रिलीफ एजेन्सी N.G.O., डिफेन्स सर्विसेज फायर सर्विस आर्डिनेन्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, माइनिंग इण्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम कम्पनी, फूड इण्डस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल, टावर कम्पनी, इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर सेफ्टी के जानकारों को बहुत अधिक मौका मिलता है



नोट: फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश-विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।

Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480



मिलावटी हल्दी से दुल्हन की मौत, घर में छाया मातम, बाजार में धड़ल्ले से बिक रही, खरीदते हुए 9 सावधानी बरतें, घर पर ऐसे करें पहचान

नयी दिल्ली। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से मिलावटी हल्दी का एक खतरनाक मामला सामने आया। यहां शादी से पहले हल्दी रस्म के दौरान दुल्हा-दुल्हन समेत कई लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हल्दी लगाने के कुछ देर बाद लोगों के शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगे। सूजन आ गई और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन-फानन में दुल्हा-दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई। प्राथमिक जांच में एलर्जी की वजह मिलावटी हल्दी बताई गई। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद मिलावटी हल्दी को लेकर देशभर में ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। अहमदाबाद नगर निगम के खाद्य विभाग ने माधुपुरा मार्केट से 2,500 किलोग्राम मिलावटी हल्दी जब्त की। वहीं कानपुर फूड डिपार्टमेंट ने चक्रेरी इंडस्ट्रियल एरिया से 398 किलो मिलावटी हल्दी पाउडर सीज किया। ऐसे में सवाल है कि कहीं हम भी मिलावटी हल्दी तो नहीं खा रहे हैं। इस लिए 'जखरत की खबर' में आज मिलावटी हल्दी की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि-मिलावटखोर हल्दी में कौन-सी चीजें मिलते हैं? मिलावटी हल्दी खाने के क्या हेल्थ रिस्क होते हैं? घर पर असली और मिलावटी हल्दी कैसे पहचानें? विषय को समझेंगे एक्सपर्ट:- देवेन्द्र कुमार दुबे, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दमोह और डॉ. अरविंद अग्रवाल, डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, श्री बालाजी

जवाब- इसे पॉइंटर्स से समझिए- नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। सवाल- मिलावटी हल्दी खाने



क्रोमेट, मेटानिल येलो, चॉक पाउडर, स्टार्च, गेहूँ का आटा, बेसन, येल्लो डाई, सिंथेटिक कलर, लकड़ी का बुरादा, लेड क्रोमेट एक पीले रंग का इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसका

मंधाना टी-20 में 600 चौके लगाने वाली पहली प्लेयर बनीं, वर्ल्डकप में छठी फिफ्टी लगाई मिताली-हरमनप्रीत को पीछे छोड़ा; दीप्ति ने झूलन की बराबरी की

स्पोर्टडेस्क। भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में 2018 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 194/5 का स्कोर बनाया था। 5. शेफाली-स्मृति में 5वीं



स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वे मंस और विमेंस टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके पुरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं। बुधवार को मंधाना ने मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने

पहली बार कोई टीम 400 रन बनाकर ऑलआउट,श्रेयस ने कोहली को पीछे किया, ईशान-गिल ने एक ही ओवर में शतक उड़ाया

लखनऊ। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम

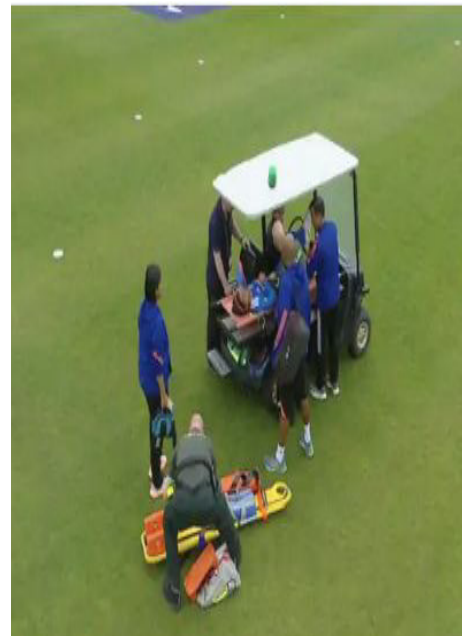


402 रन पर ऑलआउट हो गई। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 400 रन बनाने वाली टीम ऑल आउट भी हुई है। बुधवार को शुभमन गिल (154 रन) और ईशान किशन (125 रन) ने एक ही ओवर अपने-अपने शतक पूरे किए। श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। वे सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। मंच के दौरान दरविशा रसूलू को चोटिल होने पर स्टूडेंट्स से मैदान से बाहर ले जाया गया। भारत-अफगानिस्तान मैच के रिकॉर्ड्स- 1. पहली बार 2 भारतीयों

इन चीजों की मिलावट



एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली जी के साथ सवाल जवाब वे 5 माध्यम से। सवाल- मिलावटखोर हल्दी में किन चीजों की मिलावट करते हैं? जवाब- हल्दी का रंग गहरा पीला दिखाने, मात्रा बढ़ाने और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसमें कई तरह की मिलावट हो सकती है। इनमें सबसे खतरनाक लेड क्रोमेट (लेड-बेन्ड येलो पेन्ट) और मेटानिल येलो (सिंथेटिक डाई) हैं। इन्हें खाने में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा और भी कई चीजों की मिलावट हो सकती है। सवाल- हल्दी में मिलावट क्यों की जाती है? जवाब- इसका मुख्य उद्देश्य कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना है। वे इसके लिए कई बार ऐसी मिलावट करते हैं, जो सेहत वे 5 लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। मिलावटखोर अक्सर हल्दी की मात्रा बढ़ाने और उसे ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। सवाल- लेड क्रोमेट और मेटानिल येलो क्या हैं? इन्हें हल्दी में मिलाना क्यों रिस्की है? इस्तेमाल पेन्ट, प्लास्टिक और कई नॉन-फूड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसमें लेड और क्रोमियम जैसे टॉक्सिक तत्व होते हैं। कुछ मिलावटखोर हल्दी जात तो मिलावट है। रंग बहुत शाइन करे तो मिलावट है। 4. आयोडीन टेस्ट-हल्दी में कुछ बूंद आयोडीन डालो। नीला या बैंगनी रंग दिखे तो स्टार्च/ मैदा की मिलावट है। सवाल- क्या पकाने या उबालने से हल्दी में मौजूद हानिकारक तत्व खत्म हो जाते हैं? जवाब- नहीं, लेड क्रोमेट और मेटानिल येलो जैसे केमिकल्स पकाने, उबालने या भूनने से खत्म नहीं होते हैं। ये केमिकल्स हाई टेम्परेचर सहन कर सकते हैं और खाने के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। हालांकि, उबालने से बैक्टीरिया या कुछ सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं। सवाल- हल्दी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? जवाब- इस दौरान क्वालिटी और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कुछ बातों का खास खयाल रखें- हल्दी खरीदते हुए ध्यान रखें ये बातें- खुली हल्दी न ले सीलबंद पैकेट भरौसेमंद ब्रांड खरीदें। पैकिंग और सील, एक्सपायरी डेट, बहुत साइज हो तो न खरीदें/बहुत सस्ती हो सके तो हल्दी न खरीदें। साबुत हल्दी लें।



इंटरनेशनल क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत-नीदरलैंड मैच वे रिकॉर्ड्स-1. मंधाना टी-20 में 600 चौके पुरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं। 2. स्मृति की विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में छठी फिफ्टी-स्मृति ने टी-20 वर्ल्ड कप में छठवां 50लस स्कोर बनाया। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार 50लस स्कोर बनाने वाली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने हरमनप्रीत कौर और मिताली राज के 5 फिफ्टी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। 3. दीप्ति के 355 विकेट पुरे, गोस्वामी की बराबरी की-विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के 355 विकेट हो गए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में पूर्व भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी की बराबरी कर ली है। झूलन वे नाम भी 355 इंटरनेशनल क्रिकेट विकेट हैं। 4. भारत का टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर-भारतीय विमेंस टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। यह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। यह इस टूर्नामेंट में भारत का पहला 200लस स्कोर भी है। इससे पहले भारत ने



ने 80 से कम गेंद में शतक लगाया- गिल ने 77 और किशन ने 71 गेंद में शतक पूरा किया। इसके साथ ही दोनों ने भारतीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया। वनडे क्रिकेट में पहली बार दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक ही पारी में 80 या उससे कम गेंद में शतक लगाया। 2. भारत ने साउथ अफ्रीका की बराबरी की- भारत ने 8वीं बार वनडे में 400 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया। टीम ने इस मामले में साउथ अफ्रीका की बराबरी कर ली। साउथ अफ्रीका भी वनडे में 8 बार यह कारनामा कर चुका है। 4. श्रेयस अय्यर के 3 हजार वनडे रन- श्रेयस अय्यर ने 11वां रन बनाते ही वनडे में 3 हजार रन पूरे किए। उन्होंने 72 पारी और 3049 गेंद में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सबसे कम पारी में 3 हजार रन बनाने वाले विराट कोहली (75 पारी) को पीछे छोड़ दिया है। अब वे शिखर धवन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में शुभमन गिल 62 पारी के साथ पहले स्थान पर हैं। अय्यर सबसे कम गेंद में यह आंकड़ा पूरने वाले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव 2995 गेंद के साथ पहले नंबर पर हैं। 5. गिल का भारत के लिए तीसरा फास्टेस्ट 150 रन- गिल ने 108 गेंद में 150 रन पूरे किए। यह वनडे में किसी भारतीय का तीसरा सबसे तेज 150 लस का स्कोर है। पहले स्थान पर ईशान किशन हैं। उन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 103 गेंद पर 150 रन बनाए थे। 6. अफगानिस्तान के खिलाफ फास्टेस्ट सेंचुरी में ईशान और गिल शामिल-ईशान और गिल

उन्होंने सिर्फ 54 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। रहमत शाह 57 पारी के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में ईशान (71 गेंद) मंच के टॉप-4 मोमेंट्स- 1. गिल ने गले में आइस पैक पहनकर बैटिंग की-लखनऊ में मैच के दौरान काफी ज्यादा उमस थी। इसकी वजह से एक पारी में 3 ड्रिक्स ब्रेक रखे गए थे। ब्रेक में खिलाड़ी तौलिए से पसीना पोछते नजर आए। 14वें ओवर में ड्रिक्स ब्रेक के बाद कप्तान गिल ने गले में आइस पैक पहनकर बैटिंग की। 2. गिल-ईशान ने एक ही ओवर में शतक पूरे किए- भारतीय पारी के 33वें ओवर में गिल और ईशान ने अपने शतक पूरे किए। बिलाल सामी के ओवर की गिल गेंद पर चौका जड़कर पहली ने 9वां वनडे शतक लगाया। आखिरी गेंद



पर किशन ने भी चौका मारकर अपना दूसरा वनडे शतक पूरा किया। 3. नो-बॉल से टला प्रिस यादव का पहला वनडे विकेट- दूसरी पारी के 7वें ओवर में प्रिस

9.60 के रनरेट से 224 रन जोड़े। यह भारत के लिए वनडे में दूसरी सबसे तेज 200 लस रन की साझेदारी की है। इस मामले में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी पहले स्थान पर हैं। दोनों ने 2023 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ 9.82 के रनरेट से 208 रन की साझेदारी की थी। 9. अफगानिस्तान की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी हार- अफगानिस्तान को 170 रन की हार का सामना करना पड़ा। यह अफगानिस्तान की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरी सबसे बड़ी हार मिली थी। तब पर्थ के मैदान पर उसे 275 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 10. गुरबाज सबसे तेज 2 हजार वनडे रन बनाने वाले अफगानी बल्लेबाज-रहमानुल्लाह गुरबाज ने 33 गेंद पर 41 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे में 2 हजार रन भी पूरे किए। वे वनडे में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले अफगानी बन गए हैं। यादव को विकेट मिलते-मिलते रह गया। डेब्यू कर रहे प्रिस ने ओवर की 5वीं गेंद शॉर्ट डाली। गेंद रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर मिड-ऑन की ओर गई, जहां ने कैच पकड़ लिया। प्रिस अपना पहला वनडे विकेट मिलने का जश्न मना ही रहे थे। इसी दौरान नो-बॉल का हूटर बज गया। हालांकि, बाद में प्रिस ने दो विकेट निकाले। 4. दरविशा रसूलू स्टूडेंट्स के जुरिए मैदान से बाहर गए-25वें ओवर में अफगानी बल्लेबाज रसूलू को चोट के बाद रिटायर्ड हट गई। इसके बाद फिजियो ने उनके पैर पर पट्टी बांधी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। इसके बाद अफगानिस्तान के कोच रिचर्ड पायबस ने उन्हें मैदान से बाहर आने का इशारा किया। अपना डेब्यू मैच खेल रहे रसूलू को स्टूडेंट्स पर लादकर मैदान से बाहर ले जाया गया।

डेमोग्राफी की अच्छी समझ के बिना हम समस्याएं नहीं सुलझा सकते

भारत जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का ही सामना नहीं कर रहा, तेजी से बदलते

सकती है। जनसंख्या संतुलन जैसे विषय केवल प्रशासनिक या राजनीतिक विमर्श तक सीमित

सरकारें अपनी योजनाएं जनगणना, सर्वेक्षणों और पंजीकृत आबादी के आधार पर

स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान विश्वस्तरीय रिसर्च और जनसंख्या विश्लेषण के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार मुंबई के देवनार स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जनसंख्या-अध्ययन, प्रजनन-स्वास्थ्य, प्रवासन, जनसांख्यिकीय-अनुसंधान और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण अध्ययनों का प्रमुख संस्थान है। इन संस्थानों में ऐसे अनेक विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो जनसंख्या-परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों के वैज्ञानिक आकलन में सक्षम हैं। वे यह समझने में भी सहायता करते हैं कि प्रवासन की वर्तमान प्रवृत्तियां भविष्य में किन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दे सकती हैं। यही कारण है कि अनेक देशों में जनसंख्या संबंधी आयोगों और नीति समितियों में सांख्यिकीविदों, जनसांख्यिकी विशेषज्ञों, महामारी वैज्ञानिकों और प्रवासन विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। क्योंकि वे भी वैध-अवैध माइग्रेशन से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत की जनसांख्यिकीय विविधता भी व्यापक है। विभिन्न राज्यों में प्रजनन-दर, जनसंख्या-घनत्व, आयु-वितरण और प्रवासन-पैटर्न में अंतर दिखाता है। ऐसे में एक समान दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं हो सकता। क्षेत्रीय वास्तविकताओं को समझने के लिए डेटा-आधारित और वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। समिति का गठन करना गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है। किंतु जनसंख्या का प्रश्न केवल वर्तमान का नहीं, भविष्य का भी है और भविष्य की योजना तय्यो, विज्ञान और दूरदृष्टि के आधार पर ही बनाई जा सकती है। (ये लेखिका के अपने विचार हैं. डॉ. अर्चना मुकुंद)



जनसांख्यिकीय संतुलन की जटिल परिस्थितियों से भी गुजर रहा है। देश के सामने केवल यह प्रश्न नहीं है कि आबादी कितनी बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि आबादी की संरचना, वितरण, आयु-प्रोफाइल, प्रवासन-प्रवृत्तियां और संसाधनों पर उसका प्रभाव किस दिशा में जा रहा है। यही कारण है कि जस्टिस नावलेकर की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति को दूरदर्शी व समायोजक पहल माना जा रहा है। निःसंदेह समिति में प्रशासन, न्याय और नीति-निर्माण के क्षेत्र से जुड़े अनुभवी एवं विद्वान सदस्य सम्मिलित हैं। किंतु यदि इसमें प्रत्यक्ष रूप से डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता, तो यह पहल और व्यापक तथा अकादमिक रूप से समृद्ध बन

नहीं होते, बल्कि वे प्रजनन-संक्रमण, जनसंख्या-परिवर्तन, आयु-संरचना, प्रवासन-पैटर्न, निर्भरता-अनुपात, शहरीकरण प्रवृत्तियों तथा जनसंख्या-पूर्वानुमान जैसे जटिल जनसांख्यिकीय आयामों से जुड़े विस्तृत और सांख्यिकीय प्रक्षेपण की विशेषज्ञता आवश्यक होती है। यदि रोजगार-सृजन, शहरी-नियोजन और संसाधनों के प्रबंधन में संतुलन नहीं बना, तो हमारा डेमोग्राफिक डिबिडेण्ड बोल में भी परिवर्तित हो सकता है। इसी संदर्भ में अवैध प्रवासन का प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह केवल आंतरिक या सीमा सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि विकास, प्रशासन और संसाधन-प्रबंधन से भी सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है।

बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य-सुरक्षा, पेयजल, रोजगार और सामाजिक-कल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा ढांचा इसी अनुमानित जनसंख्या पर आधारित होता है। किंतु जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध आबादी जुड़ जाती है, तो वास्तविक मांग और सरकारी योजना में अंतर पैदा हो जाता है। संसाधनों का अनियोजित बंटवारा होने से अनेक योजनाएं अपने मूल उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पातीं। जब समिति का मूल विषय ही देश में जनसंख्या बदलाव से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करके स्थायी समाधान और नीतिगत उपायों का सुझाव देना है तो उसमें जनसांख्यिकी विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष भागीदारी क्यों नहीं है? भारत में इस क्षेत्र की विशेषज्ञता का अभाव नहीं है। कोलकाता

मेडिकल इमरजेंसी का अंदाजा लगाना मुश्किल, लेकिन तैयार रहना आसान

इस सोमवार रात करीब 9 बजे जालंधर के उद्योगपति दीपक पुजारा अपने बैडरूम में खेद के बीच में थे। बीते पांच वर्षों से वे उस शहर के कई लोगों की तरह फिट रहने के लिए रायजादा हंसराज बैडमिंटन स्टेडियम में कुछ घंटे खेल और मनोरंजन में बिताते थे। एक शॉट खेलते समय उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और वे गिर पड़े। दूसरे कोर्ट पर खेल रहे उसी शहर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नीतीश गर्ग उन्हें गिरता देखकर मदद के लिए दौड़े। उन्होंने कार्डियक मसाज दी, लेकिन दीपक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि अस्पताल स्टेडियम से सिर्फ दो मिनट के दूरी पर था, लेकिन डॉ. गर्ग को लगा कि दीपक इतनी-सी दूरी तक भी नहीं जा सकेगे। उन्होंने स्टेडियम की फास्ट-एड किट से एक इमरजेंसी गोली देने के बाद सीपीआर जारी रखा। साथ ही वे स्टाफ की मदद से मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस की व्यवस्था में भी लगे रहे, ताकि जल्द अस्पताल पहुंचा जा सके। जब स्टाफ दिल् को बिजली का झटका देने वाला जीवन्त उपकरण 'डिफिब्रिलेटर' लाया तो उन्होंने

झटका दिया और दिल धड़कने लगा। फिर दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में 90वें और 99वें के दो बड़े ब्लॉक मिले, जिनमें स्टेंट डाले गए। सुना है कि कि दीपक अब ट्रैटमेंट के



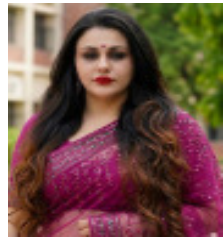
प्रति रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। इससे मुझे 2018 में दीपावली के ठीक दूसरे दिन की एक घटना याद आ गई। उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित महानंदानगर स्पोर्ट्स एरिना में कुछ डॉक्टर रिलेक्स होने के लिए बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल के बाद फोटोशूट के दौरान उनमें से एक डॉक्टर कुछ ही सेकंड में गिर पड़े। फोटो लेने वाले ने देखा कि पहली फोटो में डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, दूसरी में उनके

मुंह की स्थिति बदल गई, तीसरी में वे आगे झुक गए और चौथी फोटो में जमीन पर गिर गए। वहां मौजूद ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. निलेश मेहता ने स्थिति संभाली और रक्त प्रवाह बनाए रख सकते हैं। यह जांच लेना भी बेहतर है कि क्या आपके स्पोर्ट्स क्लब, जिम या वर्कशॉप पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (ईडी) है या नहीं। उसकी जगह पहले से पता हो तो कई कीमती मिनट बच सकते हैं। यदि आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, तब भी हर समय अपने साथ इमरजेंसी दवाएं रखने के बारे में डॉक्टर से सलाह लें। जाहिर है कि आप मौके पर किसी डॉक्टर को वो दवाएं देकर उनकी अतिरिक्त मदद कर सकते हैं। इन सभी घटनाओं से बड़ा सबक यह मिलता है कि अचानक होने वाली कार्डियक समस्या किसी के साथ, कहीं भी हो सकती है। ऐसे में जीवन का बचाना पूरी तरह तत्काल कार्रवाई पर निर्भर करता है। आप मेडिकल इमरजेंसी का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसके लिए तैयार रह सकते हैं। फंडा यह है कि एक अच्छा डॉक्टर दोस्त हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वह किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर निष्पक्ष राय देता है। लेकिन वही डॉक्टर आपका स्पोर्ट्स पार्टनर भी हो तो यह दोनों हाथों में लड़्डू होने जैसा है। एन. रघुरामन

डिग्री से नहीं, दक्षता से बनेगा भविष्य: जेन ज़ी पीढ़ी और रोजगार की नई चुनौतियाँ व्यक्ति विकास विशेषज्ञ एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) लेखिका: कौशाकी सांघी आज का दौर तेजी से बदलती तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है। ऐसे समय में केवल डिग्री हासिल कर लेना नौकरी पाने की गारंटी नहीं रह गया है। उद्योग जगत की अपेक्षाएं बदल चुकी हैं और जेन ज़ी पीढ़ी को इस बदलाव को समझने की आवश्यकता है। आज कंपनियाँ ऐसे युवाओं की तलाश में हैं जो सिर्फ शैक्षणिक रूप से योग्य न हों, बल्कि व्यावहारिक कौशल और पेशेवर दृष्टिकोण से भी मजबूत हों। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई रोजगार पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण 'एम्प्लॉयबिलिटी गैप' यानी शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच बढ़ता अंतर है। कंपनियों का मानना है कि तकनीकी ज्ञान के

साथ-साथ संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क, समय प्रबंधन, समस्या समाधान और सकारात्मक कार्य व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण



हैं। जेन ज़ी पीढ़ी तकनीक के उपयोग में निपुण है। यह पीढ़ी डिजिटल दुनिया को अच्छी तरह समझती है और नए अवसरों को तेजी से अपनाती है। लेकिन कार्यक्षेत्र पर सफलता के लिए केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं है। आज कंपनियाँ ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देती हैं जो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकें, टीम

में प्रभावी ढंग से काम कर सकें और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सकें। यही कारण है कि सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। व्यक्ति विकास, प्रभावी संवाद, इंटरव्यू कौशल, प्रस्तुतीकरण कला और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे विषय आज करियर निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम के साथ इन विषयों को भी जोड़ना चाहिए ताकि विद्यार्थी नौकरी के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। इस दिशा में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि उद्योग और शैक्षणिक संस्थान मिलकर कौशल विकास कार्यक्रम चलाएँ, तो लाखों विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक कारणों से अतिरिक्त

प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते। साथ ही, कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उद्योग की जरूरतों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण माँझूल विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए। यदि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, मेंटरशिप और करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, तो विद्यार्थी रोजगार बाजार की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे। भारत के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उन्हें सही दिशा, उचित प्रशिक्षण और उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने की है। आने वाला समय उन्हीं युवाओं का होगा जो डिग्री के साथ-साथ निरंतर सीखने, स्वयं को विकसित करने और बदलती दुनिया के अनुरूप अपने कौशल को निखारने के लिए तैयार रहेंगे। यही सफलता का नया मंत्र है और यही भारत के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव भी। कौशाकी सांघी

सार्वजनिक सड़कों पर निजी गाड़ियों का डेरा डालना कितना सही?

चुंकि घर और दफ्तर के बीच की दूरी कम है, इसलिए मैं साइकिल से ही काम पर जाती हूँ। लेकिन दक्षिणी दिल्ली के अरबिंदो मार्ग और हौज खास

लोग टैक्सी लेंगे तो निजी गाड़ी सड़क पर नहीं खड़ी रहेगी। लेकिन बड़ी सड़कों के छायादार हिस्सों में भी-सवारी की राह में, खाना खाते हुए या आराम

साल भर मुफ्त में रखने की इजाजत है। यह भी एक गंभीर मुद्दा है। अन्य देशों में सड़क पर गाड़ी खड़ी रखने के सख्त नियम हैं। यूके में जब गाड़ी अपने घर

रेवड़ी के नाम पर खूब चर्चा होती है, लेकिन सालाना गाड़ियों से हो रहे 400 करोड़ के नुकसान की कोई गिनती नहीं की जाती है। राजधानी की सड़कों को



मार्केट- जहां हम मान सकते हैं कि नियम-कानून का पालन अन्य शहरों की तुलना में ठीक ही होगा- वहां भी पड़े-लिखे अमीर गाड़ीवालों का व्यवहार अचभित करता है। हमारे तमाम शहरों में पार्किंग की सख्त कमी है। उदाहरण के लिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अहमदाबाद में 7 लाख फोर-व्हीलर हैं, लेकिन ऑथराइज्ड पार्किंग 6000 से भी कम है! जहां पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है भी (जैसे हौज खास मार्केट में सड़क पर और अंडरग्राउंड पार्किंग उपलब्ध है), वहां भी सड़क के बीच-बीच लोगों की बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। कभी-कभी लोग गाड़ी में ही बैठे, फोन पर व्यस्त रहते हैं या कुछ खा-पी रहे होते हैं, जैसे कि अपने ड्राइंग रूम में बैठे हों। क्यों? सिर्फ इसलिए कि पार्किंग के 30 रुपए उन्हें खलते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि सस्ती उबर-ओला टैक्सी से सुधार होगा।

करते हुए टैक्सी की कतारें दिखती हैं। मार्केट में सड़क पर पार्किंग ज्यादातर पैरलल नहीं है, तो सड़क का बड़ा हिस्सा गाड़ियों घेर लेती हैं। पूरा रास्ता जाम हो जाता है। साइकिल सवार इससे कम प्रभावित होते हैं। साइकिल जाम में भी निकल जाती है। आगे पहुंचने पर दिखता है कि जाम करने वाले गाड़ी मालिक/ड्राइवर पीछे परेशान लोगों से बेपरवाह आराम फरमा रहे हैं। एक की मनमर्जी कड़ियों का नुकसान करती हैं। सड़क पर पार्क करने वाली गाड़ियां यातायात को जाम कर देती हैं, वो एक पब्लिक न्यूसन्स हैं। जाम से समय की बर्बादी होती है, साथ ही पेट्रोल की खपत और प्रदूषण भी बढ़ते हैं। सड़क संकरी होने की वजह से मोटर/दोपहिया गाड़ी वालों को सड़क के बीच चलना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट का डर रहता है। देश के कई शहरों में लाखों गाड़ियों को सार्वजनिक मार्गों पर,

के बाहर सड़क पर पार्क करते हैं, तो उन्हें 3, 6 या 12 महीनों का पार्किंग परमिट खरीदना पड़ता है। इसकी कीमत गाड़ी के प्रकार के अनुसार होती है। ज्यादा प्रदूषण वाले वाहनों का परमिट महंगा है। वहां पर एक गाड़ी का सालाना पार्किंग परमिट 90-300 पाउंड तक होता है। कहने को तो दिल्ली में भी इस तरह के परमिट हैं। लेकिन मोटरगाड़ी नहीं, सड़क पर रेहड़ीवालों के लिए। हौज खास में 4 बाई 6 फीट (छोटी गाड़ी भी अंदाजन इतनी ही जगह घेरती है) की रेहड़ी का सालाना परमिट 4254 रुपए है। यदि दिल्ली की 20 लाख गाड़ियों में से आधी सार्वजनिक सड़क पर हों और उन पर यही नियम-दर लागू हो, तो लगभग 400 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होगा। 2024-25 में दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस योजना के लिए 340 करोड़ का बजट था। उस पर

देखकर कोई सोच सकता है कि पार्किंग नीति में सड़क पर 11 कैंटेगरी में से पहला अधिकार पैदल, साइकिल और दिव्यांगजन का है, फिर रेहड़ी वालों का और उसके बाद में निजी गाड़ियों के लिए पिकअप/ट्रॉप, ईवी और पेट पार्किंग है। लेकिन असल में इसका उल्टा हो रहा होता है और यह बात दूसरे शहरों के लिए भी इतनी ही सही है। कॉर्पोरेशन अतिक्रमण के खिलाफ नियमित रूप से एक्शन लेती रहती है, लेकिन सार्वजनिक मार्ग पर निजी गाड़ियों की बात कोई नहीं करता। इस हम अतिक्रमण के रूप में क्यों नहीं पहचानते? हम यह भूल जाते हैं कि सड़कें आखिरकार सार्वजनिक संपत्ति हैं। जो लाखों की गाड़ी खरीद सकते हैं, हजारों का पेट्रोल खला सकते हैं, उनसे सार्वजनिक मार्ग पर गाड़ी खड़ी करने की कुछ कीमत क्यों न वसूली जाए? (ये लेखिका के अपने विचार हैं, रीतिका खेरा)

सोशल मीडिया को लेकर दुनिया बंटी हुई है, आप किस ओर हैं?

अपने चारों ओर देखिए। आपको कई परिवार दिखेंगे, जो अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन जगत और उसके संभावित नुकसान से बचाने में जुटे हैं। उन्हें यह भी

आधिकारिक देशव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिए हैं। कई अन्य देश भी ऐसे प्रतिबंध लगाने या ऐसे कानून बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी सप्ताह यूके ने भी 16 से कम उम्र के

प्लेटफॉर्म की ओर धकेलेगा। आखिरी बार चारों तरफ देखिए। 8 से 11 साल के बच्चों के पैरेंट्स को उम्मीद है कि भारत भी इन डिजिटल प्रोडक्ट्स से बच्चों को हो रहे नुकसानों को गंभीरता

जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चे प्रतिबंधों को बायपास करने के तरीके ढूँढ लेंगे और उन्हें परेशान करने वाली कोई चीज दिखे तो भी प्रतिबंध के कारण वे पैरेंट्स



सिखा रहे हैं कि सही इस्तेमाल किया जाए तो यह उपयोगी दूत है। इस काम में उन्हें कई घंटे या कई दिन लगे होंगे, ताकि बच्चों के इस्तेमाल वाले हर डिवाइस को यथासंभव सुरक्षित बना सकें। फिर भी उन पैरेंट्स को लगता है कि बच्चों और उन सेटिंग्स पर नियमित निगरानी जरूरी है। आस-पास देखिए कि सैकड़ों पैरेंट्स ऐसे भी हैं, जो छोटे बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, ताकि वे रोजमर्रा के काम करते समय या खाना खिलाते वक्त उनको तंग न करें। यह हम जैसे पैरेंट्स को साहसी महसूस कराता है कि मानो बच्चों को 'नहीं' कहने की हिम्मत बच्चों को ऐसे व्यूरेटेट, निगरानी वाले और लामकारी अनुभवों से वंचित कर गुमाना और कम सुरक्षित सर्व मंथकेल देना' स्नैपचैट का कहना है, 'टीनेजर्स को परिवार और दोस्तों के साथ प्रवेट मैसेजिंग से दूर करना उन्हें कम सुरक्षित

बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की योजना को अंतिम रूप दिया है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि सोशल मीडिया बच्चों को दुखी कर रहा है। यह बदमाशों के लिए बच्चों को परेशान और अब्यूज करना आसान बना रहा है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर चारों तरफ नजर डालिए। मेटा, यूट्यूब और स्नैपचैट ने इस प्रतिबंध की आलोचना की है। उनका दावा है कि इससे टीनेजर्स ज्यादा हानिकारक प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे। यूट्यूब ने एक बयान में कहा कि 'सभी पर एक जैसे प्रतिबंध बच्चों को ऐसे व्यूरेटेट, निगरानी वाले और लामकारी अनुभवों से वंचित कर गुमाना और कम सुरक्षित सर्व मंथकेल देना' स्नैपचैट का कहना है, 'टीनेजर्स को परिवार और दोस्तों के साथ प्रवेट मैसेजिंग से दूर करना उन्हें कम सुरक्षित

से लेना शुरू कर देगा। वे खुश हैं कि कुछ देश साहस दिखा कर इन उत्पादों को खूली चर्चा में ला रहे हैं और इनके निर्माताओं को दिखा रहे हैं कि बहुत-से पैरेंट्स इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही, 14 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के वो पैरेंट्स तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो देख रहे हैं कि उनके बच्चों की जिंदगी मीम्स के इर्द-गिर्द घूम रही है। उन्हें लगता है कि सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की तरह उनके बच्चे भी कोई वीपीएन टूट लेंगे और मनमानी करेंगे। अब कृपया चारों ओर देखना बंद कीजिए। अपने भीतर झाँकिए। क्या कुछ पैरेंट्स की तरह आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया प्रतिबंध केवल समय की बर्बादी है और वास्तविकता में यह बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करता। क्या आपको लगता है कि यह सोशल मीडिया कंपनियों को हर

या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने में असहज महसूस करेंगे? या फिर आप मजबूती से सोचते हैं कि ये प्रतिबंध आया तो सही और भविष्य में बच्चे इन दुष्प्रभावों से बच रहेगें। मुझे लगता है कि हम सभी सोशल मीडिया के बिना बड़े हुए हैं और हमें तो कुछ नहीं हुआ। अगर बच्चे सावधानी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो यह उन्हें प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे रखने का एक बेहतर साधन है। मैं बस यह सोच रहा हूँ कि क्या इस प्रतिबंध को राहत मिल पाएगी? फंडा यह है कि क्या सोशल मीडिया प्रतिबंध कोई रामबाण इलाज है या महज एक काल्पनिक समाधान, या फिर एक ऐसी 'कैंच-22' स्थिति, जिन्हें विरोधाभासी परिस्थितियों के कारण निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता? आप इस प्रतिबंध के समर्थन में हैं या विरोध में? मुझे जरूर लिखिएगा। एन. रघुरामन

प्रियंका का आरोप- नीट स्टूडेंट्स से रु1.32 लाख करोड़ वसूले जो कि शिक्षा बजट के लगभग बराबर पसंदीदा कारोबारियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ

नयी दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्वा ने दावा किया कि हर साल नीट परीक्षा देने

बाद आई। राहुल ने बुधवार को 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत में शिक्षा

की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार बैंक खाते का वेरिफिकेशन पूरा किए बिना

एनटीए ने कहा कि अगर बैंक डिटेल्स पेडिंग होने की वजह से स्टूडेंट्स पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, तो अब तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक खाता वेरिफिकेशन बाद में पूरा कर सकते हैं और फिर भी फीस रिफंड प्रक्रिया के लिए पात्र रहेंगे। 21 जून को होगा री-एजाम-नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

री-एजाम एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया जाएगा। एनटीए के मुताबिक, दोबारा होने वाली इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।

12 जून: रीएजाम 3:15 घंटे का होगा, 4 रफ वर्क शीट मिलेंगी-एनटीए ने नीट-यूजी रीएजाम में कुछ बदलाव किए हैं। 12 जून को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ाई गई है।

12 जून: रीएजाम 3:15 घंटे का होगा, 4 रफ वर्क शीट मिलेंगी-एनटीए ने नीट-यूजी रीएजाम में कुछ बदलाव किए हैं। 12 जून को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ाई गई है।

12 जून: रीएजाम 3:15 घंटे का होगा, 4 रफ वर्क शीट मिलेंगी-एनटीए ने नीट-यूजी रीएजाम में कुछ बदलाव किए हैं। 12 जून को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ाई गई है।



वाले 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों से व्यवस्था के जरिए रु1.32 लाख करोड़ खर्च कराए जाते हैं। यह राशि देश के पूरे शिक्षा बजट रु1.40 लाख करोड़ के लगभग बराबर है। प्रियंका गांधी ने बुधवार रात एक्स पोस्ट में ये भी लिखा- मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोन माफ किए, वे 16 लाख करोड़ रुपए हैं। प्रियंका की यह टिप्पणी राहुल गांधी के कोटा दौरे के

व्यवस्था में बढ़ते दबावों पर चर्चा की थी। इधर, नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट री-एजाम वेरिफिकेशन काईड डाउनलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवार बैंक खाते का वेरिफिकेशन पूरा किए बिना भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में परीक्षा शुल्क रिफंड प्रक्रिया के लिए जरूरी बैंक खाता वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। बैंक वेरिफिकेशन बाद में करने पर भी उम्मीदवार फीस रिफंड के लिए पूरी तरह पात्र रहेंगे।

भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पहले इस शर्त के कारण कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एनटीए ने बुधवार को एक्स पोस्ट में बताया- छात्र पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में परीक्षा शुल्क रिफंड प्रक्रिया के लिए जरूरी बैंक खाता वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। बैंक वेरिफिकेशन बाद में करने पर भी उम्मीदवार फीस रिफंड के लिए पूरी तरह पात्र रहेंगे।

2 दिन में 4 नीट स्टूडेंट ने सुसाइड किया, छात्र छठी मंजिल से कूदा-तमिलनाडु की छात्रा ने लिखा- दोबारा एजाम से डर

कोयंबटूर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में नीट की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा

थापा और लखनऊ में 17 साल की एक छात्रा ने सुसाइड किया था। 12 मई को नीट परीक्षा रद्द

संविधान प्रभु सीआईटीयू से संबद्ध तस्मक ट्रेड यूनिजन के जिला सचिव हैं। दो बेटियों में

जून को री-एजाम की घोषणा से वह गहरे सदमे में आ गई थी। बुधवार सुबह उसने रिश्तेदारों को एक लंबा वॉट्सएप मैसेज भेजा। छात्रा का मैसेज पढ़ने के बाद परिजन उसके घर पहुंचे। कमरे का दरवाजा तोड़ने पर वह बेहोश मिली। उसे तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगा-छात्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी ईएएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन ने छात्रा का शव लेने से इनकार कर दिया। बाद में अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद बुधवार रात उन्होंने शव लिया। परिवार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। घटना के बाद सीपीएम के जिला समिति सदस्यों ने ईएएसआई अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और नीट पर बैं न लगाने की मांग उठाई। इधर पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक के कारण 3 मई को हुई परीक्षा रद्द हुई-नीट-यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। करीब 23 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के बाद कई राज्यों से प्रश्नपत्र लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए। जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। नीट से 1 लाख से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन-नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम ट्रेंस टेस्ट भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस,



अनुकीर्तना ने बुधवार सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले छात्रा ने अपने चाचा और करीबी रिश्तेदारों को वॉट्सएप मैसेज भेजे थे। मैसेज में उसने लिखा- 'मैंने नीट परीक्षा दी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई। अब दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है। मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, मैं अब उनका सामना कैसे करूंगी, नहीं जानती।' वहीं, अहमदाबाद के न्यू रानीप इलाके में बुधवार रात करीब 2:30 बजे 17 साल के छात्र ने आनंदम फ्लैट्स के छलांग लगा दी। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पिछले दो दिनों में नीट स्टूडेंट की आत्महत्या का यह चौथा मामला है। इससे पहले 16 जून को देहरादून में 23 साल की रिया

होने के बाद देश भर में अब तक लगभग 12 स्टूडेंट्स जान दे चुके

अनुकीर्तना बड़ी थी। उसने एडमिशन के एक प्राइवेट स्कूल

अनुकीर्तना बड़ी थी। उसने एडमिशन के एक प्राइवेट स्कूल



हैं। कोयंबटूर स्थित घर के कमरे में बेहोश मिली थी छात्रा-अनुकीर्तना कोयंबटूर के कोयंबटूर स्थित पार्क टाउन की रहने वाली थी। उसके पिता

से 12वीं तक पढ़ाई की थी। डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना उसका सपना था। हालांकि, पेपर लीक के कारण नीट परीक्षा रद्द होने और 21

बीडीएस, आयुष (बीएएमएस, बीएचएमएस) और नर्सिंग जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है, जिसमें एम्स और जिपमर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं।

जून को री-एजाम की घोषणा से वह गहरे सदमे में आ गई थी। बुधवार सुबह उसने रिश्तेदारों को एक लंबा वॉट्सएप मैसेज भेजा। छात्रा का मैसेज पढ़ने के बाद परिजन उसके घर पहुंचे। कमरे का दरवाजा तोड़ने पर वह बेहोश मिली। उसे तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगा-छात्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी ईएएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन ने छात्रा का शव लेने से इनकार कर दिया। बाद में अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद बुधवार रात उन्होंने शव लिया। परिवार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। घटना के बाद सीपीएम के जिला समिति सदस्यों ने ईएएसआई अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और नीट पर बैं न लगाने की मांग उठाई। इधर पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक के कारण 3 मई को हुई परीक्षा रद्द हुई-नीट-यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। करीब 23 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के बाद कई राज्यों से प्रश्नपत्र लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए। जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। नीट से 1 लाख से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन-नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम ट्रेंस टेस्ट भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस,

ईरान को रु28 लाख करोड़ हर्जाना, कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, डील के 14-पॉइंट्स की पूरी डिटेल

साथ ही 60 दिनों की यह समयसीमा शुरू हो गई है। आगे की खबर पेज संख्या 07 पर... वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 60 दिनों की

उसी अंतिम समझौते में यह तय किया जाएगा कि 300 अरब डॉलर का फंड कैसे बनाया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा और उसे किस तरह खर्च किया जाएगा। दस्तावेज

अपने पास मौजूद लगभग 11 टन संवर्धित परमाणु सामग्री को कम घनत्व वाला बनाए। इसे डाउन-ब्लेंडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि यूरेनियम को इतना

ने वादा किया है कि वह ईरान के उन धन और संपत्तियों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगा, जो अभी तक विभिन्न प्रतिबंधों के कारण फ्रीज्ड हैं या जिन पर रोक लगी



यह समयसीमा काफी छोटी मानी जा रही है। अमेरिकी अधिकारी भी निजी तौर पर मानते हैं कि इतने कम समय में अंतिम समझौते तक पहुंचना आसान नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान के साथ पहले हुई परमाणु वार्ताओं में कई साल लग चुके हैं। हालांकि ट्रम्प प्रशासन ने जानबूझकर यह महत्वाकांक्षी समयसीमा तय की है। अगर 60 दिनों के भीतर कोई अंतिम समझौता हो जाता है, तो यह अमेरिका के मध्यवाधि (मिडटर्म) चुनावों से पहले राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि साबित हो सकती है। ऐसे समय में जब उनकी घरेलू लोकप्रियता में गिरावट देखी जा रही है, यह समझौता उन्हें राजनीतिक फायदा भी पहुंचा सकता है। पॉइंट-4: अमेरिका समुद्री नाकेबंदी हटाएगा-अमेरिका दस्तखत के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यह नाकेबंदी 30 दिनों के भीतर पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के बाद ईरान फिर से अपने बंदरगाहों से तेल और अन्य सामान निर्यात कर सकेगा। साथ ही दूसरे देशों से आने वाला माल भी बिना बड़ी रुकावट के ईरान पहुंच सकेगा। यह ईरान के लिए बहुत बड़ी और तत्काल राहत होगी, क्योंकि उसके ज्यादातर निर्यात चीन को जाते हैं। जैसे ही निर्यात दोबारा शुरू होगा, ईरान के पास विदेशी मुद्रा और राजस्व आना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी मौजूदा आर्थिक मुश्किलें काफी हद तक कम हो सकती हैं। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। नाकेबंदी हटाने से अमेरिका अपने सबसे प्रभावी दबाव के साधनों में से एक खो देगा। पॉइंट-5: होमजुज स्टूट को फिर से खोला जाएगा-समझौते पर दस्तखत होते ही ईरान ने वादा किया है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी और इस दौरान जहाजों से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस समझौते की सबसे अहम लाइन है- सिर्फ 60 दिनों तक बिना किसी फीस के। इसका मतलब है कि अगले 60 दिनों तक ईरान होमजुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से इस तरह का पैसा नहीं लेता था। इसलिए अगर भविष्य में फीस लगाई जाती है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा और होमजुज से गुजरने वाली वैश्विक समुद्री व्यापार लागत बढ़ सकती है। पॉइंट-6: ईरान को रु28 लाख करोड़ का हर्जाना-समझौते के तहत अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर (28 लाख करोड़ रुपए) की योजना तैयार करने का वादा किया है। हालांकि यह पैसा तुरंत नहीं दिया जाएगा। पहले अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और व्यापक समझौते पर पहुंचना होगा।

में यह भी कहा गया है कि इस योजना को लागू करने के लिए जरूरी सभी लाइसेंस, छूट और वित्तीय मंजूरीयां अमेरिका देगा, ताकि निवेश और धन के लेनदेन में कानूनी बाधाएं न आएँ। राष्ट्रपति ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि इस फंड में अमेरिका सीधे पैसा नहीं लगाएगा। हालांकि, उन्होंने यह संभावना जरूर खुली छोड़ी कि खाड़ी देश, जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई इस फंड के लिए पैसा उपलब्ध करा सकते हैं। पॉइंट-7: ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे-समझौते के मुताबिक, अमेरिका ने अंतिम समझौता होने पर ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को एक-एक करके खत्म करने का वादा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देना शायद वह सबसे बड़ा कदम है, जिसके बदले अमेरिका ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करने के लिए राजी कर सकता है। यही व्यवस्था 2015 के परमाणु समझौते में भी अपनाई गई थी। उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंध स्वीकार किए थे और बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी। हालांकि उस समझौते में लगी पाबंदियों की अवधि अधिकतम 15 साल थी। लेकिन ट्रम्प का कहना है कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमेशा के लिए प्रतिबंध चाहते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि दोनों देश इस बात पर सहमत कैसे होते हैं कि कौन-कौन से प्रतिबंध हटाए जाएंगे और उन्हें किस समय हटाया जाएगा। साथ ही यह भी तय करना होगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के कौन-कौन से कदम कब उठाएगा। पॉइंट-8: ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा-समझौते में ईरान ने एक बार फिर बयान दिया है कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और न ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम (एनरिचड यूरेनियम) के भंडार का क्या किया जाएगा, इस पर दोनों देश मिलकर फैसला करेंगे। इसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाएगी, जिस पर आगे की बातचीत में सहमति बनेगी। फिलहाल न्यूनतम सहमति यह है कि इस संवर्धित सामग्री को ईरान के भीतर ही इस तरह बदला जाएगा कि उससे परमाणु हथियार बनाना संभव न रहे। यह पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की निगरानी में होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह समझौते का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार सीधे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात की गई है। यही मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और युद्ध की सबसे बड़ी वजह रहा है। हालांकि इस पॉइंट में सबसे विवादित मुद्दों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। दस्तावेज में ईरान ने फिर से कहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। ईरान 1970 में परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने के समय यही वादा कर चुका था। बाद में 2015 के परमाणु समझौते में भी उसने यही कहा था कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। समझौते में ईरान से कहा गया है कि वह

पतला कर दिया जाए कि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में न हो सके। इन 11 टन सामग्री में करीब 970 पाउंड ऐसा यूरेनियम भी शामिल है, जिसे 60फीसदी तक एनरिचड किया जा चुका है। यह स्तर परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी स्तर के काफी करीब माना जाता है। लेकिन समझौते में यह नहीं कहा गया है कि ईरान को यह सामग्री देश से बाहर भेजनी होगी। ईरान लंबे समय से अपने यूरेनियम भंडार को विदेश भेजने का विरोध करता रहा है। हालांकि 2015 के परमाणु समझौते में ईरान ने अपने उस समय के लगभग 97 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम भंडार को रूस भेज दिया था। यही कारण है कि अभी कई बड़े सवाल अनसुलझे हैं। जैसे कि क्या ईरान अपने पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार रख पाएगा? क्या उसे अपनी प्रमुख परमाणु सुविधाएं बंद करनी होंगी? क्या उसे नया यूरेनियम संवर्धित करने की अनुमति मिलेगी? या उसे 13 से 20 साल तक संवर्धन गतिविधियां रोकनी पड़ेंगी? पॉइंट-9: दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं करेंगे-समझौते में कहा गया है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अभी जिस स्तर पर चला रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ाएगा। वह नए बड़े कदम नहीं उठाएगा और न ही अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे बातचीत के लिए एक स्पष्ट शुरुआती स्थिति तय हो जाती है। इसका मकसद यह है कि अंतिम समझौता होने तक अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर अतिरिक्त दबाव डालकर नई रियायतें हासिल करने की कोशिश न करें। यानी बातचीत के दौरान न तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और न ही अमेरिका नए प्रतिबंध लगाएगा या क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य ताकत भेजेगा। पॉइंट-10: ईरानी सामानों के निर्यात पर छूट-समझौते के मुताबिक, एमओयू पर दस्तखत होते ही अमेरिका ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़े अन्य सामानों के निर्यात पर राहत देना शुरू कर देगा। इसके लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय जरूरी छूट और मंजूरीयां जारी करेगा, ताकि ईरान अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सके। यह राहत सिर्फ तेल बेचने तक सीमित नहीं होगी। इसमें बैंकिंग लेन-देन, बीमा, जहाजरानी, माल ढुलाई और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़ी बाधाओं को भी कम किया जाएगा, जो ईरान के तेल निर्यात में रुकावट बनती रही हैं। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक समझौते का यह हिस्सा ईरान के खिलाफ सख्त रुख रखने वाले नेताओं और विशेषज्ञों के बीच सबसे ज्यादा चिंता का कारण बना हुआ है। उनका मानना है कि तेल निर्यात पर लगी रोक से जुड़े समझौते के मामले में हुआ था, जिसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के एक प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अंतिम समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच का राजनीतिक समझौता नहीं रहेगा, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी। यदि सुरक्षा परिषद इस समझौते को मंजूरी देती है, तो इसके प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की ताकत मिल जाएगी और दुनिया के अन्य देशों को भी उसका सामना करना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे समझौते को मजबूती मिलेगी, जैसा कि पिछले वर्ष जापान के जूडो समझौते के मामले में हुआ था, जिसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला था। हालांकि कई एक्सपर्ट्स को शक है कि यह चरण वास्तव में आएगा भी या नहीं।

हूई है। हालांकि यह पैसा कब और किस प्रक्रिया के तहत जारी होगा, इसका तरीका अमेरिका और ईरान आपसी बातचीत के जरिए तय करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसका मतलब यह हो सकता है कि अंतिम समझौता होने का इंतजार किए बिना ही ईरान के लिए अरबों डॉलर की रकम जारी होना शुरू हो जाए। अनुमान है कि यह राशि 24 अरब डॉलर या उससे भी अधिक हो सकती है। पॉइंट-12: दोनों देश मिलकर निगरानी व्यवस्था बनाएंगे, जो यह देखेगी कि एमओयू की सभी शर्तों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। यह सिस्टम इस बात की जांच करेगा कि-ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वादों का पालन कर रहा है या नहीं। अमेरिका प्रतिबंधों में राहत और अन्य आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है या नहीं। दोनों पक्ष समझौते की समयसीमा और शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका यह तय करना चाहता है कि ईरान के हर वादे की स्वतंत्र रूप से जांच और पुष्टि की जा सके। यानी केवल ईरान के वादे करना पर्याप्त नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि यह साबित भी किया जा सके कि ईरान वास्तव में अपना परमाणु कार्यक्रम, संवर्धित यूरेनियम के भंडार और अन्य प्रतिबद्धताओं से जुड़े समझौते का पालन कर रहा है। पॉइंट-13: तुरंत सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू नहीं होगी-सबसे पहले दोनों देशों को समझौते के कुछ अहम बिंदुओं को लागू करना होगा। इनमें युद्धविराम बनाए रखना, होमजुज जलडमरूमध्य को खोलना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, तेल निर्यात पर राहत देना और ईरान की जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच बहाल करना जैसे कदम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पता चलता है कि आने वाले दौर की बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे अहम विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही होगा। परमाणु गतिविधियों की सीमा क्या होगी, एनरिचड यूरेनियम का क्या होगा, निरीक्षण व्यवस्था कैसी होगी और प्रतिबंध किस तरह हटाए जाएंगे, जैसे सवाल अभी पूरी तरह तय नहीं हुए हैं। पॉइंट-14: अंतिम समझौते को यूएनएससी मंजूरी देगी-जब अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता हो जाएगा, तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के एक प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अंतिम समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच का राजनीतिक समझौता नहीं रहेगा, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी। यदि सुरक्षा परिषद इस समझौते को मंजूरी देती है, तो इसके प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की ताकत मिल जाएगी और दुनिया के अन्य देशों को भी उसका सामना करना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे समझौते को मजबूती मिलेगी, जैसा कि पिछले वर्ष जापान के जूडो समझौते के मामले में हुआ था, जिसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला था। हालांकि कई एक्सपर्ट्स को शक है कि यह चरण वास्तव में आएगा भी या नहीं।

